रणजीत टाइम्स

इंदौर

शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026

वर्ष 02 | अंक 250 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

पोलिश पीएम भारत आए,मोदी से की मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने 'गुड महाराजा' का किया जिक्र

उन्होंने पोलैंड के 1,000 बच्चों को शरण दी थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। इस मुलाकात में दोनों देशों के पुराने रिश्तों की झलक भी दिखी। मोदी ने 'गुड महाराजा' का जिक्र किया। यह नाम जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा को दिया गया था, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के करीब 1,000 बच्चों को भारत में शरण दी थी। **भारत बना था 5000 पोलिश बच्चों का दूसरा घर-** 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ के हमलों के बाद पोलैंड पर



कब्जा हो गया। हजारों पोलिश नागरिक बेघर हो गए, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। 1942 में नवानगर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जामनगर के पास बालाचड़ी में करीब 1,000 पोलिश बच्चों को शरण दी। उनके रहने, खाने, पढ़ाई और इलाज का इंतजाम किया गया। बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने का मौका भी दिया गया। इसी मदद के कारण पोलैंड में महाराजा को 'डोब्री महाराजा' यानी 'गुड महाराजा' कहा जाने लगा। भारत में पोलिश शरणार्थियों को दूसरी जगहों पर भी शरण मिली। 1943 में कोल्हापुर रियासत के वलीवडे शिविर में करीब 5,000 पोलिश शरणार्थी रहे। यहां उनके लिए स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं थीं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ।

16 साल बाद भारत आए डोनाल्ड टस्क

पोलैंड के प्रधानमंत्री 16 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं। इससे पहले 2010 में अपने पहले कार्यकाल में वह भारत आए थे। टस्क के साथ करीब 100 पोलिश कंपनियों का कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। पोलैंड 2030 तक भारत के साथ सालाना कारोबार दोगुना करना चाहता है। दिल्ली में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद टस्क 23 अक्टूबर को बेंगलुरु जाएंगे। वहां वे सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे।

एमपी के बीना में बनेगी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री

सालाना 22 लाख टन प्रोडक्शन होगा,ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा



भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में पेट्रोकेमिकल उद्योग के विस्तार से प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीना में 50 हजार करोड़ की लागत वाली डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परियोजना से हर साल 22 लाख टन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होंगे। इससे इन उद्योगों को जरूरी कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में करीब 12 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय इंडिया केम-2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनके साथ दीप प्रज्ज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर 'केमिकल फ्रेटरनिटी रिपोर्ट' पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आयोजन में देश-विदेश के रसायन, पेट्रोकेमिकल, पॉलिमर और एग्रोकेमिकल उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बीना से लेकर आष्टा तक पेट्रोकेमिकल उद्योग का विस्तार- मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए बिजली, पानी, जमीन और प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बीना की परियोजना के अलावा विजयपुर में गेल का आधुनिक गैस प्रसंस्करण ढांचा और सीहोर जिले के आष्टा में गेल इंडिया की पेट्रोकेमिकल परियोजना भी औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ा रही हैं।

2040 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश का केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल बाजार करीब 120 अरब डॉलर का था, जो अब दोगुने से अधिक हो चुका है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच इस क्षेत्र में करीब एक लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की बात भी उन्होंने कही। डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच भारत के पास नए औद्योगिक अवसर विकसित करने का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2040 तक देश के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश पूरी भागीदारी करेगा।

फडणवीस बोले- राज्यों में निवेश के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश के राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और ओडिशा के मुख्यमंत्री का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी राज्य अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश लाकर देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं।

फ्रांस दंगों से जुड़े भारत में हुए प्रदर्शनों के तार

रिपोर्ट में दावा-चीन में बैठा सिंघम कर रहा फंडिंग

9 देशों के 101 संगठनों तक फैला सीक्रेट नेटवर्क



नई दिल्ली (एजेंसी)। फ्रांस में हुए दंगों और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच कनेक्शन का दावा किया गया है। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में 9 देशों के 101 संगठनों के नेटवर्क का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये संगठन अलग-अलग देशों में प्रदर्शनों के आयोजन, उनके बीच तालमेल बनाने या उन्हें बढ़ावा देने में भूमिका निभा रहे हैं। इसमें फ्रांस के इंडियन अलायंस पेरिस और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल जैसे संगठनों का भी नाम है।

फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध का दावा

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट 'ग्लोबल केऑस इंक ग्रोज टू 101 ग्रुप्स' में इंडियन अलायंस पेरिस और मैनहैटन स्थित पीपल्स फोरम के बीच साझेदारी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिसइन्फोलैब ने अपनी एक पोस्ट में दावा किया कि सचिव जॉय बनर्जी फ्रांस की ट्रेड यूनियन के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं और उनके फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध हैं।

कांग्रेस अगले 30 साल तक सत्ता में नहीं आएगी

● वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी को अमित शाह की दो टूक ● कहा-प्रदर्शन और धरने से कुछ नहीं होगा,जनता के बीच जाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 8,941 करोड़ की लागत वाली दिल्ली जल बोर्ड की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकारों पर सीवर का पानी यमुना में छोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने विपक्ष



के वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दे को लेकर पलटवार भी किया। अमित शाह ने कहा, दिल्ली में एक अलग खेल चल रहा है। लगातार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चुनकर आ रही है। उनको पेट में दर्द है, इसलिए इन्होंने वोट चोरी का बहाना बनाया। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों वोट से चुनकर नहीं आती। वोट चोरी करती है।

2014 से 30 तक आपकी सरकार देश में नहीं बनने वाली है:गृहमंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब मैं कहता हूं कि 30 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी तो ये जनता को कहते हैं कि देखो वोट चोरी है वरना अमित शाह जी को कैसे मालूम पड़ा। अमित शाह तो यहां जन्मा है, यहां रहता है और यहीं मरेगा, मुझे हर 6 महीने में विदेश नहीं जाना पड़ता है। मैं तो देश की जनता के बीच में रहता हूं। आप जिस तरह से नाकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि 2014 से 30 तक आपकी सरकार कभी नहीं बनने वाली है। चुनाव आयोग पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे आरोपों पर शाह ने कहा कांग्रेस केरल में जीतती है, तो ईसी ठीक।

607 किलोग्राम अवैध गांजा जप्त

सलीम हुसैन

झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमे झाबुआ एसपी द्वारा एनडीपीआरएस के मामले को लेकर दोहरी सफलता मिली जिसमें कालीदेवी थाना ओर पेटलावद थाना क्षेत्र से अवैध गांजा उत्पादन को लेकर 607 किलोग्राम गांजे के पौधे जप्त किए गए जिसमें जप्त गांजे की कीमत 60 लाख 30 हजार रूपए पुलिस बताई जा रही है साथ ही पुलिस अधीक्षक झाबुआ देवेन्द्र पाटीदार का कहना है कि कालीदेवी पुलिस द्वारा मुखबिर कि सूचना पर ग्राम छापरी गोपाल पिता रत्ना मोरी के खेत पर दबिश के दौरान 80.15 किलोग्राम गांजा





प्राप्त हुआ जिसकी कीमत 7लाख 61 हजार 425 रूपए बताई जा रही है इस कार्यवाही में आरोपी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश पुलिस अभी कर रही है वहीं पेटलावद थाना अंतर्गत आने वाली सारंगी चौकी पर भी मुखबिर कि सूचना पर ग्राम हिम्मतगढ़ निवासी आरोपी गलिया पिता भेरू डामर के खेत के पास कपास ओर तुवर कि फसल के बीच अवैध गांजे कि खेती कि जा रही थी जहां से पेटलावद पुलिस ने 526.94 किलोग्राम वजनी गाँजे के जिंदा पौधे बरामद किए जिसकी कीमत लगभ 52 लाख 69 हजार 400 रुपए बताई जा रही है इन दोनों कार्यवाहियों में झाबुआ एसडीओपी श्रीमती मोनिका सिंह,कालीदेवी थाना प्रभारी निरीक्षक रमेशचन्द्र भास्करे, एसडिओपी पेटलावद सुश्री अनुरती सबनानी,पेटलावद थाना प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह भूरिया और दोनों थाना क्षेत्र कि टीम कि सराहनीय भूमिका रही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों ओर अवैध कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है ओर जल्द जल्द झाबुआ जिले से पूरी तरह नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार खत्म करने की दिशा में ओर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लोकायुक्त कार्यवाही

सलीम हुसैन

झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिस पर आज लोकायुक्त की गाज गिरी तड़के 11 बजे के समय पर शिकायत के बाद बीईओ झाबुआ जयनारायण बैरागी के दफ्तर में अपने 8 माह का बकाया वेतन निकालने की तय बात पर शिकायतकर्ता धूम सिंह पिता पुनसिंह सिंगड़ अधीक्षक शासकीय बालक छात्रावास सेमलिया बड़ी द्वारा आरोपी जय नारायण बैरागी ओर सह आरोपी पवन सिंह बिलवाल सहायक ग्रेड 3 को 10 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा लोकायुक्त



पुलिस इन्दौर के इंस्पेक्टर आशुतोष मिठास ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शिकायतकर्ता धूमसिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर में जाकर आवेदन के माध्यम शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें पर्याप्त साक्ष्य होने पर ट्रैप की कार्यवाही को आज अंजाम दिया गया वहीं से ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर जय नारायण बैरागी ओर पवन सिंह बिलवाल को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही के लिए झाबुआ स्थानीय सर्किट हाउस ले जाया गया जा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत धारा 7/20 अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।



मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत ग्यारसपुर की 25 ग्राम पंचायतों में आज शुक्रवार को लगेंगे शिविर

धर्मेन्द्र गुप्ता

नौलास और गूलरखेड़ी क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में होगी जनसमस्याओं की सुनवाई विदिशा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिले की ग्यारसपुर जनपद पंचायत के नौलास और गूलरखेड़ी क्लस्टर की 25 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार 23 अक्टूबर को शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। नौलास क्लस्टर की 12 ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम पंचायत बंडवा, खेजड़ापड़रयात, बोरीरामपुर, घटेरा, झिरनिया, बरखेड़ा गंभीर, लखूली, नौलास, पूरागोसाई, सीहोद, सियासी और कंजेला शामिल हैं। इसी प्रकार गूलरखेड़ी क्लस्टर की जिन 13 ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन होगा उनमें ग्राम पंचायत बर्रीघाट, गूलरखेड़ी, ऐरन, चक्क रघुनाथपुर, धतुरिया, अंडिया कला, गुलाबगंज, इकोडिया, मढ़ी चौबीसा, पिपरिया, संतापुर, मुंगवारा और गुनुआ शामिल हैं।

अभियान के 20 विषयों पर होगा विशेष फोकस - सीएम हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई में प्राप्त भ्रमण क्षेत्र की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज भ्रमण क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण। अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण। न्यायालयीन आदेश होने के उपरांत भी राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं होने संबंधी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण। सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी का निर्माण सुनिश्चित करना। सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड का निर्माण सुनिश्चित करना। समग्र आईडी की ई केवायसी तथा आधार कार्ड निर्माण अपडेशन के प्रकरणों का निराकरण। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता की समीक्षा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल की उपलब्धता तथा टंकी निर्माण की स्थिति की समीक्षा। आंगनवाड़ी का निरीक्षण एवं कुपोषण से मुक्ति हेतु आंगनवाड़ी में बच्चों के वजन और ऊँचाई के मापन की स्थिति। स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण एवं वहाँ डॉक्टर्स, पेरामेडिकल स्टॉफ, दवाएं, उपकरण आदि की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रदाय की स्थिति की जांच। स्कूल, कॉलेज का निरीक्षण एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति और अध्ययन की गुणवत्ता का निरीक्षण। क्षेत्र में खाद-बीज एवं अन्य आदानों की उपलब्धता की समीक्षा। स्थानीय राशन की दुकान का निरीक्षण एवं आम जनता से फीडबैक लेना। विभिन्न शासकीय परिसंपत्तियों जैसे - सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जलजीवन मिशन अंतर्गत निर्मित संरचनाऐं, भवन, खेत, फसल आदि की स्थिति का निरीक्षण। शासकीय संस्थाओं जैसे - आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समिति, तहसील, कृषि उपज मण्डी, मदिरा दुकान, पुलिस थाना, लोक सेवा केन्द्र,शासकीय देवस्थान, औद्योगिक क्षेत्र आदि का निरीक्षण। खाद-बीज की दुकान, एजेन्सी, गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक, पटाखा लायसेंस धारियों की दुकानें, गोदाम, अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं की डीलरशिप, निजी विदयालय आदि का निरीक्षण।

रणजीत टाइम्स

नियमों की सरेआम धज्जियां

रात के अंधेरे हो या दिन पिकअप वाहन पर ठंस-ठंसकर बैठे लोग, केबिन की छत पर भी बैठे बच्चे और युवा

महेन्द्र मालवीय। रणजीत टाईम्स

यातायात नियमों के पालन और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से किए जा रहे दावों के बावजूद ग्रामीण इलाकों और मुख्य सड़कों पर खतरनाक सफर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर मालवाहक वाहनों में यात्रियों के असुरक्षित परिवहन की गंभीर समस्या को उजागर करती है।

केबिन की छत से लेकर डंपर बॉडी तक खतरा

तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि रात के समय एक सफेद रंग का मालवाहक पिकअप वाहन खड़ा है, जिसके पीछे बने माल ढाने वाले हिस्से (डाले) में कई लोग खचाखच भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा नियमों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए कई लोग और बच्चे ड्राइवर केबिन के ठीक ऊपर (छत पर) खतरनाक तरीके से बैठे नजर आ रहे हैं। वाहन के ऊपर लोहे/लकड़ी के



फ्रेम के सहारे बिना किसी सुरक्षा घेरे के बैठे ये लोग जरा सी अनहोनी पर सीधे सड़क पर गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।

रात के समय बढ़ जाता है हादसों का जोखिम

ऐसे तो दिन में भी (मालवाहक) लोडिंग वाहनों में ठुस ठुस कर लोगो वाहन के अन्दर कैबिन पर बैठाया जा रहा है लेकिन रात के अंधेरे में अधिकतर इस तरह मालवाहक गाड़ियों में सवारी भरकर ले जाना बेहद जानलेवा साबित होता है। अक्सर त्योहारों, धार्मिक आयोजनों या पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च में सफर करने के चक्कर में लोग मालवाहक पिकअप वाहनों का सहारा लेते हैं। लेकिन इस तरह केबिन की छत और ओवरलोड सवारियां बैठाना मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन है।

प्रशासन और पुलिस पर उठते सवाल

»» क्या मुख्य मार्गों पर गश्त करने वाली पुलिस टीम और यातायात विभाग की नजर इन ओवरलोड मालवाहकों पर नहीं पड़ती?

»» माल ढोने के लिए पंजीकृत वाहनों में इस तरह यात्रियों का जोखिमभरा परिवहन करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?

सख्त चेकिंग और कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन केवल चालानी कार्रवाई तक सीमित न रहकर रात के समय सघन चेकिंग अभियान चलाए और ऐसे मालवाहक वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई करे, ताकि समय रहते किसी संभावित बड़े हादसे को रोका जा सके।

खकनार के बिजोरी में

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा 7 लाख का सीसी रोड

6 महीने में ही उखड़ी गिट्टियां, लीपापोती की तैयारी में जिम्मेदार

ग्राम पंचायत बिजोरी का मामला: अधिकारियों की चौखट तक पहुंची शिकायतें, फिर भी बेखबर बना जिला प्रशासन

महेन्द्र मालवीय रणजीत टाईम्स

बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिजोरी में विकास कार्यों के नाम पर शासकीय धनराशि के दुरुपयोग और अनियमितता का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बिजोरी में लगभग 7 लाख रुपये की लागत से निर्मित सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए इस रोड की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि महज़ छः महीने के भीतर ही यह पूरी तरह से जर्जर और उखड़ने लगा है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब बिजोरी में इस तरह का घटिया निर्माण हुआ हो। पंचायत में पूर्व में हुए कई अन्य निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, तो भ्रष्टाचार की



एक बड़ी परत उधड़ सकती है।

अधिकारियों को संज्ञान, फिर भी कार्रवाई से गुरेज

रोड के पूरी तरह खराब हो जाने और ग्रामीणों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी के बावजूद ज़िम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रोड को दुरुस्त करने या दोषियों पर कार्रवाई करने की ज़हमत नहीं उठाई गई। मामले में जब पंचायत के सचिव दीपक अंबिकर से बात की गई, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि "यदि रोड खराब बना है, तो इसमें केवल मेरी अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है।" सचिव के इस बयान ने पंचायत के कामकाज के तरीके पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि जब रोड पूरी तरह से गुणवत्ताहीन था, तो उपयंत्री ने किस आधार पर इसका लाखों रुपये का मूल्यांकन पास कर दिया? इस पूरे मूल्यांकन प्रक्रिया की गहन जाँच होनी चाहिए।

पुराने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए नई लीपापोती की तैयारी!

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बिजोरी में अब नए सीसी रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल से लेकर नदी की ओर जाने वाले इसी बदहाल और जर्जर रोड पर लीपापोती कर मामले को रफा-दफा करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि पुराने घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। ग्राम पंचायत बिजोरी के जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से माँग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए। 7 लाख रुपये की लागत से बने रोड के मूल्यांकन की तकनीकी जाँच कराई जाए और दोषी सरपंच, सचिव व उपयंत्री के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा से भाजपा के पेट में दर्द क्यों :- पंकज जैन

धर्मेन्द्र गुप्ता

विदिशा : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी द्वारा उज्जैन से अयोध्या तक निकाली जा रही सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री पंकज जैन ने कहा कि यदि सनातन धर्म भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, तो उसके सम्मान और स्वाभिमान की बात करने पर भाजपा जैसे राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए,



श्री जैन ने कहा की सनातन धर्म किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और जीवन-पद्धति से जुड़ा विषय है। ऐसे में सनातन की बात करने का अधिकार भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को भी है। श्री जैन ने आरोप लगाया कि भाजपा लंबे समय से हिंदुत्व और सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दों को अपनी राजनीति में प्रमुखता देती रही है, ऐसे में यदि श्री दिग्विजय सिंह भी सनातन स्वाभिमान की बात करते हैं, तो भाजपा उसे राजनीतिक चश्मे से देखने लगती है, आखिर सनातन के मुद्दे पर भाजपा नेताओं का दोहरा मापदंड क्यों ?

इंदौर फल-सब्जी मंडी का आयुक्त ने किया निरीक्षण, यातायात व्यवस्था और पारदर्शी नीलामी पर जोर

खुशबू श्रीवास्तव

मंडी में प्रतिदिन 30 से 35 हजार लोगों और 8 से 10 हजार वाहनों का होता है आवागमन, किसानों के हित में काम करने के निर्देश

इंदौर। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आयुक्त सह प्रबंध संचालक राघवेन्द्र सिंह (IAS) ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी, इंदौर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और किसानों एवं व्यापारियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मंडी सचिव ओ.पी. खेड़े से मंडी में प्रतिदिन होने वाले आवागमन की जानकारी ली।



सचिव ने बताया कि मंडी परिसर में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार लोगों का आवागमन होता है। इसके साथ ही 8 से 10 हजार वाहन प्रतिदिन मंडी में आते-जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना आवश्यक है।

पारदर्शी नीलामी और किसान हित पर जोर

निरीक्षण के दौरान आयुक्त राघवेन्द्र सिंह ने निर्देश दिए कि फल एवं सब्जियों की आवक-जावक के समय यातायात व्यवस्था सुगम रखी जाए, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित करने और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। इस दौरान आयुक्त ने उपस्थित किसानों से चर्चा कर मंडी की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण में मंडी बोर्ड भोपाल एवं इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर और मंडी कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण में प्रमुख रूप से मंडी बोर्ड के अधीक्षण यंत्री मधुकर पंवार, संयुक्त संचालक प्रवीण वर्मा, मंडी समिति इंदौर के सचिव ओ.पी. खेड़े, कार्यपालन यंत्री पी.एल. घाघरे, सहायक यंत्री कमलाकर सिंह बघेल, उपयंत्री मनोज चौधरी, निज सहायक अनिल कुमार चौरे तथा फल-सब्जी मंडी के प्रभारी राधेश्याम ठाकुर मौजूद रहे।

ध्यान हमें कठिनतम परिस्थितियों में सहज व प्रसन्न रहना सिखाता है



सहजयोग ध्यान करने की एक अर्वाचीन पद्धति है। जो आज के तनावग्रस्त जीवन में बहुत कारागर साबित हो रही है। आपको ऐसा लगेगा की योगा, ध्यान आदि बुढापे में करने की चीजें हैं परंतु ऐसा नहीं है, आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी तनाव में रहते हैं, कुछ न कुछ समस्याओं से घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सहजयोग सीखने के बाद और इस ध्यान मे पारंगत होने के बाद आपके जीवन में समस्यायें नहीं आयेंगी। समर्थ रामदास महाराज कहते हैं ('मना त्वाचिरे पूर्वसंचित केले तयासारखे भोगणे प्राप्त झाले') जो कुछ भी शारिरिक या मानसिक भोग हैं वो आपके जीवन में रहेंगे परंतु आप अंदर से इतने शक्तिशाली बन जायेंगे कि उन सभी समास्याओं से प्रभावित न होते हुए आप आसानी से उनसे छूटकर आनंददायी जीवन व्यतीत करने लगेंगें। आपके जीवन में सकारात्मकता व प्रसन्नता का गुणांक कई गुना बढ़ जाएगा। सहजयोग ध्यान अत्यंत सहज है। प.पूज्य श्री माताजी कहते हैं कि जो साधक अपने आत्म साक्षात्कार को सच्चे हृदय से चाहेगा उसे तत्क्षण ये प्राप्त हो जाएगा।और इसे प्राप्त करने बाद धीरे-धीरे साधक इस ध्यान की सूक्ष्मताओं को समझकर अपना जीवन सकारात्मक तरीके से बदलने के लिये सदैव प्रयासरत रहता है। कंठोपनिषद में वर्णित है कि यह मनुष्यरूपी शरीर ग्यारह द्वारोंवाला है और ये शरीर ही उस आत्म रूपी परमेश्वर की नगरी है। वह आनंदस्वरूप परमात्मा सर्वत्र समभाव से सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूपी इस मनुष्य शरीर के हृदयप्रासाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य इसी जन्म में इस आत्मसाक्षात्कार को पाना चाहते हैं और जो साधक इस शाश्वत सत्य को जानता है वह शोक के कारण रूप संसार बन्धन से छूटकर जन्ममृत्यु के चक्र से सदा के लिये छूट जाता है। यही ब्रम्हसाक्षात्कार है। वर्तमान में मे इसे पाना सहज हो गया है, बस आपको अपने आत्मसाक्षात्कार की शुद्ध इच्छा कर हर दिन सुबह-शाम १० मिनट इस ध्यान में स्थित होना होता है और आपकी एकाकारिता परमात्मा से होने लगती है और जीवन में सभी प्रकार के समाधान प्राप्त हो जाते हैं। सहजयोग से संबंधित जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्णतया निशुल्क है। टोल फ्री नं – 1800 2700 800
बेवसाइट - sahajayoga.org.in

कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश

धर्मेन्द्र गुप्ता

विदिशा। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज जिला चिकित्सालय विदिशा का औचक निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएनसी वार्ड एवं बर्न वार्ड का अवलोकन किया तथा वहां भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार व्यवस्था एवं चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों से उपचार की गुणवत्ता, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाइयों की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक



सुविधाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि मरीजों को बेहतर,- गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सालय प्रबंधन व विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वार्डों में स्वच्छता, उपचार व्यवस्था तथा मरीजों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार एवं सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान विदिशा एसडीएम श्री मनीष कुमार जैन, सिविल सर्जन सहित अन्य चिकित्सीय स्टॉफ मौजूद रहा।

विजयादशमी पर कोठी गांव में रंगमंच और शीतला मंदिर निर्माण की घोषणा

स्थानीय कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोककला और पारंपरिक नाचा की प्रस्तुति से बांधा समां, जिला पंचायत सभापति लेखराज ध्रुव हुए शामिल

छुरा। छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र के अंतिम ग्राम पंचायत कोठी में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव में धार्मिक आस्था के साथ छत्तीसगढ़ की लोककला और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सभापति लेखराज ध्रुव शामिल हुए। आयोजन



के दौरान गांव में रंगमंच निर्माण और शीतला मंदिर निर्माण की घोषणा की गई, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। विजयादशमी के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी लोककला पर आधारित पारंपरिक नाचा रहा। नवसृजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की लोकपरंपराओं, ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत करने का प्रयास किया। स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। गांव में आयोजित इस कार्यक्रम ने धार्मिक उत्सव के साथ लोकसंस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। ग्रामीण अंचलों में दशहरा जैसे पर्व केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक एकता, आपसी मेल-मिलाप और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का माध्यम भी बनते हैं। कोठी गांव में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। वहीं, रंगमंच निर्माण की घोषणा से भविष्य में गांव के कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थायी मंच उपलब्ध होने की उम्मीद है। शीतला मंदिर निर्माण की घोषणा को भी ग्रामीणों की धार्मिक आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। कार्यक्रम में दामोदर सोरी, श्यामलाल सोरी, गुलाब सोरी, सहदेव विश्वकर्मा, किरण विश्वकर्मा, चैतराम नागेश, अरविंद जायसवाल, जगदेव मरकाम, कतीराम, भीमसेन, गंगाराम, दिलीप, बसंत, यशवंत, नैनसिंह, बल्ला, ओमकार, लांछन, आनंद, दवाद राम, दयालाल, केक्तू राम, विजय, कलीराम, सोनसाय, पुराणिक, शोहद्रा बाई, गीता, मीना और सुनती सहित अन्य ग्रामीणों की सहभागिता रही।

त्योहार में सड़कों की खुदाई, जाम में फंसा शहर; दुकानदारों का धंधा चौपट

अब कलाली मोहल्ला से मिशन अस्पताल तक सड़क खोदी, छावनी और जूनी इंदौर की सड़कें भी बदहाल

● अग्रसेन चौराहे से जगन्नाथ धर्मशाला का रास्ता पहले से बंद, आखिर जाएं तो जाएं कहां?





इंदौर। त्योहार के सीजन में बाजारों में रौनक होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की अदूरदर्शिता के कारण शहर के कई प्रमुख रास्तों पर चल रही खुदाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अब निगम ने कलाली मोहल्ला से मिशन अस्पताल तक सड़क खोद दी है। छावनी वाली सड़क पहले से खुदी पड़ी है, वहीं जूनी इंदौर की सड़क के भी यही हाल हैं। अग्रसेन चौराहे से जगन्नाथ धर्मशाला तक जाने का रास्ता पहले ही बंद है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर निकलें तो निकलें कहां से? एक के बाद एक रास्ते बंद होने और सड़कों की खुदाई के कारण क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। जाम में फंसकर राहगीरों को परेशान होना पड़ रहा है। त्योहार के दौरान खरीदारी के लिए निकलने वाले लोग भी समय पर बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका सीधा असर दुकानदारों के कारोबार पर पड़ रहा है। ग्राहक जाम और रास्तों की परेशानी से बचने के लिए बाजार आने से कतरा रहे हैं, जिससे व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा है। सड़क निर्माण और विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन त्योहार के सीजन में एक साथ कई प्रमुख रास्तों की खुदाई और मार्ग बंद होने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

सवाल यह है कि क्या खुदाई शुरू करने से पहले वैकल्पिक रास्तों और यातायात प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था की गई? क्या दुकानदारों, स्कूली बच्चों और स्थानीय रहवासियों की परेशानी का आकलन किया गया? अधिकतर सड़कों की खुदाई से स्कूल आने जाने वाले छोटे बच्चों और उनके पालको को भी परेशान उठाना पड़ रही है सड़क के कारण ऑटो, बस और अन्य स्कूली वाहन नही आ रहे है। विकास कार्यों के नाम पर जनता को जाम और बदहाल रास्तों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। संबंधित विभागों को काम की समयसीमा तय करने, खुदाई वाले हिस्सों पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और वैकल्पिक मार्गों की स्पष्ट व्यवस्था करने की जरूरत है। त्योहार के बीच कारोबार, आवाजाही और बच्चों की सुरक्षा को यूं ही नजरअंदाज किया गया तो परेशानी और बढ़ेगी।

अब लर्निंग लायसेंस बनावाना होगा मुश्किल

आरटीओ के नियमों में बदलाव

● लायसेंस का फर्जी वाड़ा रोकने के लिए कैमरे से होगी निगरानी

इंदौर। आरटीओ ऑफिस में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब नई टेक्नॉलॉजी से आवेदक के स्थान पर अन्य व्यक्ति परीक्षा नही दे सकेगा।खास कर एजेंट जो ओटीपी लेकर लर्निंग लायसेंस बनवा देते थे वह अब नही बन सकेंगे। आज से इस नई व्यवस्था में टेस्ट के दौरान कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से आवेदक की पहचान की जाएगी। इससे एजेंटों के माध्यम से परीक्षा पास कराने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी तथा पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनेगी। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के लिए लर्नर लाइसेंस टेस्ट का एक नया मॉड्यूल तैयार किया है। इस प्रणाली में फेस ऑथेंटिकेशन और कैमरा आधारित निगरानी की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के उद्देश्य से सैफ एग्जाम ब्राउजर का उपयोग होगा जिससे टेस्ट के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। मौजूदा व्यवस्था में आवेदकों के आधार विवरण और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को एजेंटों के साथ साझा किए जाने की शिकायतें आती रही हैं। अधिकतर मामलों में एजेंट आवेदक से ओटीपी प्राप्त करके खुद ही ऑनलाइन परीक्षा देकर उसे पास करा देते हैं। इस वजह से लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति के यातायात नियमों के वास्तविक ज्ञान का पता नहीं चल पाता है।

वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन परीक्षा में 10 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से पास होने के लिए 6 सही जवाब देना अनिवार्य है। नई प्रणाली में कैमरा निगरानी और पहचान सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि परीक्षा केवल वास्तविक आवेदक ही दे। लर्निंग लाइसेंस वाहन चलाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य आवेदक के यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बुनियादी ज्ञान का परीक्षण करना है। यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी के स्थान पर परीक्षा देता है तो इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है। नया मॉड्यूल परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा लर्नर लाइसेंस की ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जानकारी भेज दी है। एनआईसी द्वारा विकसित यह नया मॉड्यूल वर्तमान में ट्रायल के दौर से गुजर रहा है और इसे 23 अक्टूबर से पूरी तरह लागू करने की योजना बनाई गई है।

1.75 लाख अवैध नल कनेक्शन, अब कटेगी पानी चोरो की लाइन

इंदौर। इंदौर शहर में 1.75 लाख अवैध नल कनेक्शन है जिससे पानी की चोरी कर निगम को राजस्व का चूना लग रहा है। यह आंकड़ा नगर निगम के अपने रिकॉर्ड में दर्ज है। अब तक अवैध कनेक्शनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाने वाला निगम सख्ती की तैयारी में है। सालों से बंद पड़ी अवैध नल कनेक्शन वैध करने की मुहिम दोबारा शुरू होगी। पहले लोगों को नोटिस देकर कनेक्शन वैध कराने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया तो सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी। इंदौर में औसत से 14 इंच कम बारिश के चलते आने वाली गर्मी में जलसंकट की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ निगम शहरवासियों से पानी बचाने की अपील कर रहा है, दूसरी तरफ लाखों अवैध कनेक्शनों के जरिए पानी की चोरी रोकने की चुनौती सामने है। ऐसे में निगम ने अवैध कनेक्शनों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन में जलप्रदाय विभाग इस मुहिम की योजना बना रहा है। योजना के तहत बस्तियों में रहने वाले लोग 2500 रुपए और कॉलोनियों में रहने वाले लोग 6000 रुपए शुल्क जमा कराकर अपने अवैध नल कनेक्शन वैध करा सकेंगे। इसके लिए पहले नोटिस जारी किए जाएंगे, ताकि लोग कार्रवाई से पहले कनेक्शन नियमित करा लें। तय प्रक्रिया के बावजूद कनेक्शन वैध नहीं कराने वालों पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

कम बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूं की जगह दलहन-तिलहन को बढ़ावा देने पर जोर

● खरीफ की समीक्षा और रबी की तैयारियों पर संभाग स्तरीय बैठक, खाद-बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा



इंदौर। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में संभागायुक्त कार्यालय में खरीफ 2026 की समीक्षा और रबी 2026-27 की तैयारियों को लेकर संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त भास्कर लक्षकार सहित इंदौर संभाग के सभी आठ जिलों के कलेक्टर और कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खेतों की नमी का उपयोग करते हुए समय पर बुवाई करने और उत्पादन प्रभावित होने से बचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही रबी सीजन के लिए खाद, बीज और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने बताया कि बैठक का उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना, जनजातीय क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करना और किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों से जोड़ना है।

पुष्प ब्रांड को हाईकोर्ट से झटका, जब्ती का एकतरफा आदेश निरस्त

कॉपी-पेस्ट तरीके से आदेश पर निचली अदालत की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी



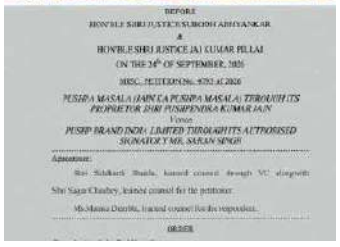

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुष्प ब्रांड इंडिया लिमिटेड को झटका देते हुए कमर्शियल कोर्ट द्वारा पारित एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा और जब्ती का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की युगलपीठ ने बिना पक्ष सुने और तथ्यों का समुचित मूल्यांकन किए यांत्रिक तरीके से आदेश पारित करने पर निचली अदालत की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

क्या है मामला – पुष्प ब्रांड इंडिया लिमिटेड ने इंदौर की स्थानीय कंपनी 'जैन का पुष्पा मसाला' के प्रोपराइटर पुष्पेंद्र कुमार जैन पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वाणिज्यिक वाद दायर किया था। कमर्शियल कोर्ट ने 22 जून 2026 को एकतरफा आदेश जारी कर लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और संबंधित उत्पादों की जब्ती तथा बिक्री पर रोक लगा दी।

30 दिन के बजाय 57 दिन बाद की तारीख – याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सागर चौबे और सिद्धार्थ शुक्ला ने हाईकोर्ट में पैरवी की। दलील दी गई कि सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 3ए के तहत 30 दिनों में निराकरण के प्रावधान के बावजूद अगली सुनवाई 18 अगस्त को रखी गई। याचिकाकर्ता ने नायरा चॉकलेट्स मामले में भी इसी तरह का आदेश दिए जाने का मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट ने याचिका (एमपी नंबर 4795/2026) स्वीकार करते हुए 22 जून का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी में न्यायाधीश की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में प्रतिकूल प्रविष्टि की संभावना का उल्लेख किया और मामले को प्रशासनिक स्तर पर देखने की बात कही। इससे 'जैन का पुष्पा मसाला' को राहत मिली।

कृषि समीक्षा बैठक में कलेक्टर दंपती का अनोखा संयोग

इंदौर। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में एक अनोखा संयोग देखने को मिला। बैठक में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और उनकी पत्नी एवं बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह एक साथ शामिल हुईं। दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों का प्रस्तुतीकरण दिया। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में खाद-बीज की उपलब्धता और रबी सीजन की तैयारियों की जानकारी दी, जबकि बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों में कपास और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने से जुड़े सुझाव रखे। महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में कलेक्टर दंपती की एक साथ मौजूदगी चर्चा का विषय रही। दोनों 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।



गंभीर संगठित अपराध बना

मानव तस्करी

युवतियों के मानव तस्करों के गिरोह के चंगुल में फंसने के समाचार आए दिन आते ही रहते हैं। शायद यही कारण रहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे मानव तस्करी रोकने के लिए बनाई गई विशेष इकाइयों को थाने का दर्जा दें। वेश्यावृत्ति या देह व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली मानव-तस्करी एक गंभीर संगठित अपराध है। आम तौर पर कोई भी महिला स्वेच्छा से इस व्यवसाय में कदम नहीं रखती। हालांकि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, फिर भी कुछ प्रविधान ऐसे हैं, जिनके तहत वेश्यावृत्ति करने वाले को भी सजा दी जा सकती है। हैरानी है कि अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए कानून है, परंतु इसमें मानव-तस्करी की परिभाषा नहीं दी गई। भारतीय दंड विधान में भी जस्टिस वर्मा कमेटी की अनुशंसाओं के बाद 2013 में मानव तस्करी के प्रविधान (धारा 370 और धारा 370 ए आइपीसी) जोड़े गए, जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन यानी पालेरमो प्रोटोकाल के अनुरूप हैं। 1956 का कानून संयुक्त राष्ट्र की 1949 के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन पर आधारित था, जिसका उद्देश्य यौन शोषण को रोकना था। दो बार इस कानून में संशोधन किया गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत भी मानव तस्करी को संगठित अपराध माना गया। बालकों की तस्करी के प्रकार पोक्सो और जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार निपटाए जाते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिलों में मानव-तस्करी विरोधी इकाइयां भी सक्रिय हैं, जिन्हें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता दी गई है। कानून में कुछ कमियों को दूर करने और मानव-तस्करी की पीड़ित की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसी विषय पर काम करने वाली संस्था प्रज्वला ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। यह याचिका केंद्र सरकार द्वारा कुछ कार्रवाई करने के वादे के चलते कोर्ट द्वारा निपटाई गई।

अंकिता हत्याकांड: उर्मिला सनावर को सीबीआई का नोटिस

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

23 अक्टूबर को देहरादून अदालत में पेशी, नार्को और पॉलीग्राफ जांच पर देनी होगी सहमति



अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को नोटिस जारी किया है। उन्हें 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देहरादून स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। सहारनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम ने बुधवार को नोटिस सौंपा। जांच एजेंसी ने उर्मिला का नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण कराने के लिए अदालत में आवेदन किया है। अदालत में यह स्पष्ट किया जाएगा कि वह इन परीक्षणों के लिए बिना दबाव, धमकी या लालच के स्वेच्छा से सहमति दे रही हैं या नहीं। जांच का एक प्रमुख पहलू मामले से जुड़ी कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग और उसमें उठाए गए सवाल हैं। उर्मिला पहले ही परीक्षण कराने की सहमति देने की बात कह चुकी हैं।

गौरतलब है कि सितंबर 2022 में ऋषिकेश के निकट एक रिसॉर्ट में कार्यरत अंकिता की हत्या हुई थी। मामले में दोषियों को उम्रकैद हो चुकी है, लेकिन कथित विशिष्ट व्यक्ति की भूमिका से जुड़े सवालों की जांच जारी है। नार्को परीक्षण अभी हुआ नहीं है। इसकी प्रक्रिया और वैधानिक शर्तें पूरी होना जरूरी है।

अस्पताल में रिश्वत का खेल, डॉक्टर समेत दो गिरफ्तार



रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

टेंडर रद्द होने से बचाने और बिलों के भुगतान में सहूलियत देने के नाम पर मांगी थी घूस

दिल्ली के पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल में कथित रिश्वतखोरी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने डॉक्टर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अस्पताल का टेंडर रद्द होने से बचाने और लंबित बिलों के भुगतान में मदद करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में अस्पताल का औषधि विशेषज्ञ और एक पर्यवेक्षक शामिल हैं। दोनों को कथित तौर पर एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायत मिलने के बाद जांच एजेंसी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। मामले में रिश्वत की मांग, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। अस्पताल जैसी जनसेवा की संस्था में यदि ठेकों और बिलों का रास्ता रिश्वत से तय होता है, तो यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, आरोपों की अंतिम

चार्जशीट नहीं मिली तो निलंबन खत्म नहीं: हाईकोर्ट

यौन उत्पीड़न के आरोपी अधिकारी को राजस्थान उच्च न्यायालय का झटका, केवल तकनीकी आधार पर राहत नहीं



रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी अधिकारी को आरोपपत्र नहीं मिलने भर से उसका निलंबन अपने आप रद्द नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र की तामील में कमी और निलंबन की वैधता दो अलग-अलग सवाल हैं। केवल इस आधार पर निलंबन समाप्त नहीं माना जा सकता। मामले में अधिकारी ने आरोपपत्र नहीं मिलने का हवाला देकर निलंबन को चुनौती दी थी। अदालत ने इस दलील को स्वतः राहत का पर्याप्त आधार नहीं माना। निलंबन की वैधता संबंधित सेवा नियमों, मामले के तथ्यों और सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई के आधार पर तय होगी। फैसले का संदेश साफ है—विभागीय कार्रवाई में प्रक्रियागत नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन किसी तकनीकी कमी से हर स्थिति में निलंबन समाप्त नहीं होता। हालांकि, निलंबन को सही ठहराना आरोपों को साबित करना नहीं है। आरोपों का अंतिम निर्धारण विधिसम्मत जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग: तीन आरोपी 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत मे



हथियारों की तलाश और साजिश का खुलासा करने में जुटी मुंबई अपराध शाखा

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को एस्प्लेनेड अदालत में पेश किए गए आरोपियों को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आरोपियों की पहचान रेहान उर्फ सुक्का, रितिक कुर्मी उर्फ रोशन और फूल सिंह के रूप में हुई है। तीनों को राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया था।

पुलिस ने अदालत से 14 दिन की हिरासत मांगी थी। जांच दल का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करना, कथित साजिश की कड़ियां जोड़ना और हमले का मकसद पता लगाना जरूरी है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दो मोबाइल फोन भी नष्ट किए। बचाव पक्ष ने हिरासत बढ़ाने का विरोध किया और कहा कि आरोपियों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। 18 अक्टूबर को जुहू में हुई गोलीबारी में टाइगर को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उनके चालक और एक राहगीर घायल हुए। मामले में हत्या के प्रयास और शस्त्र कानून के तहत प्रकरण दर्ज है।

आधार: अदालत की कार्यवाही और प्रकाशित समाचार विवरण।

60 करोड़ की हेरोइन जब्त, सात गिरफ्तार

बौद्धिक प्रतिकार
www.boudhikpratikar.com



नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिले के विशेष दस्ते ने चार राज्यों में फैले कथित हेरोइन तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर 8.128 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई गई है।

गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मण हुड्डा, अनिल उर्फ भोला, बबलू, रुकसार अली उर्फ राजू, अजाज अहमद, मोहम्मद अजहर और प्रकाश कुमार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, जांच की शुरुआत 16 सितंबर को दिल्ली के बेगमपुर से हुई, जहां लक्ष्मण हुड्डा से 300 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद अनिल उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया। जांच लखनऊ के जानकीपुरम स्थित कथित अवैध निर्माण इकाई तक पहुंची।

वहां से 6.275 किलोग्राम तैयार हेरोइन और रसायन जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, नेटवर्क की कड़ियां हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैली थीं। प्रकाश कुमार पर अवैध अफीम खेती से जुड़े होने का आरोप है। नकदी, वाहन और निर्माण उपकरण भी जब्त हुए। मामले में आगे की जांच जारी है।

ऑनलाइन बाजार की चमक दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट!

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

मोबाइल पर सस्ती खरीदारी की होड़ में मोहल्ले की दुकानें कैसे टिकेंगी? बाजार बढ़ रहा है, मगर छोटे व्यापारियों की कमाई का सवाल अनसुना नहीं रह सकता।

भारत का ऑनलाइन खुदरा बाजार इस वर्ष 90 अरब डॉलर पार करने का अनुमान है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत है, लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है—जब ग्राहक घर बैठे सामान मंगाएगा, तो गली-मोहल्ले का दुकानदार अपना घर कैसे चलाएगा? जिस किराना दुकानदार ने वर्षों में ग्राहक का भरोसा कमाया, दुकान का किराया दिया, माल खरीदा और परिवार की रोजी-रोटी इसी कारोबार से जोड़ी, उसके सामने अब भारी पूंजी वाली कंपनियों की चुनौती है। आकर्षक छूट, मुफ्त वितरण और मिनटों में सामान पहुंचाने की प्रतिस्पर्धा में छोटा दुकानदार आखिर कितनी दूर तक टिकेगा? एक उपभोक्ता सर्वेक्षण में 300 किराना दुकानदारों में से 67 प्रतिशत ने त्वरित आपूर्ति सेवाओं के आने के बाद बिक्री घटने की बात कही। वहीं 74 प्रतिशत ने इसे दीर्घकालिक खतरा माना। यह आंकड़ा चेतावनी है, हालांकि इसे देश की हर दुकान की स्थिति नहीं माना जा सकता। सवाल ऑनलाइन खरीदारी रोकने का नहीं, निष्पक्ष मुकाबले का है। छोटे दुकानदारों को डिजिटल मंच, उचित ऋण, सामूहिक खरीद और स्थानीय वितरण की सुविधा मिले। बड़ी कंपनियों की मूल्य नीति और प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता पर भी निगरानी जरूरी है। आर्थिक तरक्की का पैमाना सिर्फ ऑनलाइन बिक्री नहीं, उन करोड़ों परिवारों की आजीविका भी होनी चाहिए, जिनकी दुकानें देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं।

विक्रांत पर राफेल की तैयारी, गोवा में शुरू हुआ परीक्षण

समुद्र में नौसेना की मारक ताकत बढ़ाने की कवायद, 26 लड़ाकू विमानों का सौदा



रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

भारतीय नौसेना ने गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का परीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत से इन विमानों के संचालन के लिए जरूरी बदलावों और तकनीकी अनुकूलता की जांच करना है। परीक्षण गोवा स्थित आईएनएस हंसा के तटीय परीक्षण केंद्र में चल रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि विक्रांत पर विमान उड़ान भरने के लिए ढलानदार प्रक्षेपण पट्टी और उतरने के लिए विशेष अवरोधक तारों की व्यवस्था है। परीक्षणों में विमान की उड़ान, उतरने और विमानवाहक पोत की परिचालन जरूरतों के अनुरूप बदलावों का आकलन किया जा रहा है। विमान के बड़े फैलाव और जहाज पर सीमित जगह को देखते हुए कुछ छोटे बदलावों पर भी विचार है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपये का समझौता किया है। इनमें 22 लड़ाकू और चार प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। आपूर्ति 2030 तक पूरी करने का लक्ष्य है। इन विमानों से समुद्री निगरानी, हवाई सुरक्षा और दुश्मन के ठिकानों पर हमले की क्षमता बढ़ेगी। पुराने मिग-29के बेड़े की सीमाओं के बीच यह खरीद महत्वपूर्ण है। हालांकि, असली ताकत विमानों की तैनाती, रखरखाव और युद्धक तैयारी से तय होगी।

ड्रोन और स्वायत्त तकनीक पर वायुसेना का बड़ा दांव

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

करीब 100 उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रक्षा जरूरतों का रोडमैप, स्वदेशी निर्माण पर जोर



भारतीय वायुसेना ने ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के विकास को गति देने के लिए उद्योग जगत के साथ नई पहल की है। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उद्योग संवाद कार्यक्रम में ड्रोन कंपनियों और उनके सहयोगी उद्योगों के करीब 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों से उद्योगों को अवगत कराना और स्वदेशी तकनीक के विकास में साझेदारी बढ़ाना रहा। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका, निगरानी, टोही और मानवरहित अभियानों की जरूरतों ने इन प्रणालियों का महत्व बढ़ा दिया है। वायुसेना ने 21 अक्टूबर को जारी संवाद में स्वदेशी इंजन, स्वायत्त संचालन के सॉफ्टवेयर, मजबूत दिशानिर्देशन और मानकीकृत तकनीकी प्रणालियों को प्राथमिकता दी। वायुसेना का लक्ष्य अलग-अलग क्षमताओं वाले मानवरहित विमानों का ऐसा नेटवर्क तैयार करना है, जो मौजूदा और भविष्य के लड़ाकू विमानों के साथ काम कर सके। इससे निगरानी, टोही और अभियान संबंधी क्षमताओं को विस्तार मिल सकता है। लेकिन रोडमैप साझा करना और वास्तविक सैन्य तैनाती दो अलग चरण हैं। तकनीकी विश्वसनीयता, उत्पादन क्षमता, लागत और युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रदर्शन ही इस योजना की असली परीक्षा होंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का दावा तभी मजबूत होगा, जब भारतीय कंपनियां आयातित उपकरणों पर निर्भरता घटाकर भरोसेमंद तकनीक विकसित करें और उसे समय पर उपलब्ध कराएं।

अमिताभ बच्चन ने काम और सामाजिक माध्यमों से लिया विराम



सख्त आराम और स्वस्थ होने की सलाह का किया जिक्र, प्रशंसकों में चिंता

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों के लिए काम और सामाजिक माध्यमों से दूरी बनाने की जानकारी साझा की है। उनके इस फैसले के बाद प्रशंसकों के बीच उनकी सेहत को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमिताभ ने अपने संदेश में सख्त आराम और स्वस्थ होने की सलाह का उल्लेख करते हुए माफी भी मांगी। हालांकि, उनके संदेश से किसी गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि नहीं होती। उनकी परेशानी की विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी भी सामने नहीं आई है। अमिताभ बच्चन लंबे समय से फिल्मों, टेलीविजन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में उनका अचानक विराम लेना प्रशंसकों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलों के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना उचित होगा। काम से यह अस्थायी दूरी उनके स्वास्थ्य और आराम को प्राथमिकता देने का संकेत है।

एमपी में एक राज्यसभा सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव



मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई है सीट, 26 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना

भोपाल। केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे से मध्यप्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026 को) चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। इस सीट पर 12 नवंबर को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। मुरुगन का राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, 26 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर तय की गई है। 3 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 5 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 230 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 116 मतों का कोटा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं।

भोपाल के होटल में अब पहचान छिपाना होगा मुश्किल

होटल में कौन ठहरा, पहचान असली या नकली, बारकोड से होगा सत्यापन

भोपाल। राजधानी के होटलों में गलत नाम-पते या फर्जी पहचान-पत्र के सहारे ठहरने वालों की पहचान करना अब पहले से आसान हो सकता है। भोपाल पुलिस होटल, लॉज और धर्मशालाओं में आने वाले मेहमानों के सत्यापन के लिए 'अतिथि ऐप' आधारित व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत प्रायोगिक तौर पर एमपी नगर थाना क्षेत्र से की जाएगी। योजना सफल



रही तो इसे शहर के दूसरे इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत होटलों और ठहरने के दूसरे स्थानों पर विशेष बारकोड उपलब्ध कराया जाएगा। मेहमान को अपने मोबाइल से इसे स्कैन करना होगा। इसके माध्यम से आधार का ऑफलाइन सत्यापन करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य पहचान-पत्रों की प्रामाणिकता जांचना और गलत पहचान के सहारे ठहरने वाले लोगों की पहचान में मदद करना है। अभी होटल संचालक मेहमानों से पहचान-पत्र लेकर उनके विवरण दर्ज करते हैं। लेकिन केवल दस्तावेज की प्रति रख लेने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि इस्तेमाल किया गया पहचान-पत्र वास्तविक है या उसमें दी गई जानकारी सही है। नई व्यवस्था में बारकोड के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाने की तैयारी है। इससे पहचान-पत्र की जांच में मदद मिल सकती है और फर्जी दस्तावेज के सहारे ठहरने के मामलों को पकड़ना आसान हो सकता है।

फर्जी पहचान से छिपने वालों पर क्यों है नजर

होटल में ठहरने वाले व्यक्ति की पहचान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पुलिस जांच का अहम हिस्सा होती है। अगर कोई आरोपी गलत नाम या फर्जी दस्तावेज के सहारे ठहरता है, तो उसकी तलाश में पुलिस को अतिरिक्त समय लग सकता है। भोपाल में सामने आए ऐसे मामलों ने भी डिजिटल सत्यापन की जरूरत को चर्चा में ला दिया है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एमपी नगर थाना क्षेत्र से शुरू करने की तैयारी है। शुरुआती चरण में व्यवस्था की उपयोगिता, तकनीकी दिक्कतों और होटल संचालकों को होने वाली परेशानियों का आकलन किया जा सकेगा। इसके बाद जरूरी बदलाव कर इसे दूसरे थाना क्षेत्रों तक बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। भोपाल पुलिस की इस पहल का असर इस बात से तय होगा कि बारकोड स्कैन करने की प्रक्रिया कितनी आसान और विश्वसनीय रहती है तथा इससे फर्जी पहचान के मामलों में जांच कितनी प्रभावी होती है।

नगरीय निकायों में खरीदी मामले की हाईलेवल जांच कराएगी सरकार

मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा-कीमतों में इतना अंतर क्यों,इसकी भी जांच होगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी के दौरान कीमतों में भारी अंतर सामने आने के मामले में सरकार ने उच्चस्तरीय जांच कराने की बात कही है। नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि विभाग के कामकाज की निगरानी होती है। खरीदी या निर्माण कार्य में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाती है। एसीएस संजय दुबे के वायरल वीडियो के जरिए जो जानकारी सामने आई है, उसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि GeM पोर्टल पर खरीदी में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। किसी उत्पाद की कीमत में इतना अंतर क्यों है, इसकी पड़ताल होगी। यह भी देखा जाएगा कि पोर्टल की प्रक्रिया में मौजूद कमियों का फायदा कैसे उठाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी में गड़बड़ी मिलने पर सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री बोलीं- कीमतों में अंतर की वजह भी पता करेंगे- वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछे जाने पर प्रतिमा बागरी ने कहा कि विभाग में खरीदी और निर्माण सहित सभी कामों की निगरानी होती है। गड़बड़ी



मिलने पर विभाग जांच करता है और कार्रवाई भी करता है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है और जरूरत पड़ने पर उसकी सूची उपलब्ध कराई जा सकती है। मंत्री ने कहा,'अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके माध्यम से जानकारी मिली है। हम इसकी उच्चस्तरीय जांच कराएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी व्यक्ति संलिप्त होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।' जब उनसे पूछा गया कि खरीदी में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि सभी पर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे का वायरल वीडियो भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में हुई विभागीय बैठक का बताया जा रहा है। बैठक में नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संचालक और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। वीडियो में संजय दुबे ने नगरीय निकायों की खरीदी में कीमतों के अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग को पता है कि किस निकाय ने क्या खरीदा और किस दर पर खरीदा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस साल से गड़बड़ियों पर कार्रवाई होगी। करीब तीन मिनट बाद MPSEDC के एडिशनल एमडी अंशुमन राज ने GeM पोर्टल से हुई खरीदी का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 2023 में एक नगर पालिका में 200 LED बल्ब रू. 60 लाख में खरीदने की शिकायत से यह विश्लेषण शुरू हुआ था। इसके बाद प्रदेश के नगरीय निकायों की खरीदी का डेटा जुटाया गया। प्रस्तुति के मुताबिक, पिछले तीन साल में 374 नगरीय निकायों ने GeM पोर्टल से करीब रू. 1,134 करोड़ की खरीदी की। अंशुमन राज ने दावा किया कि यदि खरीदी औसत दर पर होती तो करीब रू. 250 करोड़ बचाए जा सकते थे।

सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस के लिए एमपी को राष्ट्रीय सम्मान

भोपाल। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) को वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस (2.60 प्रतिशत) दर्ज करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। कंपनी को यह सम्मान लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने इस उपलब्धि पर एमपी ट्रांसको के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रदेश की सुदृढ़ विद्युत ट्रांसमिशन व्यवस्था, तकनीकी दक्षता, नवाचारों और निरंतर सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लॉस को न्यूनतम रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना



प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। एमपी ट्रांसको की ओर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरसी शर्मा एवं वसंत कर्नाड ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त इस प्रतिष्ठित मंच से दिया जाने वाला यह पुरस्कार पावर सेक्टर की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका पावर लाइन द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली विद्युत कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। वेस्टर्न रीजन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और गोवा सहित पांच राज्य शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।